ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(1): 217-219
www.allresearchjournal.com
Received: 25-11-2016
Accepted: 28-12-2016

मधु कुमारी
ग्रा0 + पो0– वासुदेवपुर, जिला– समस्तीपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मधु कुमारी
ग्रा0 + पो0– वासुदेवपुर, जिला– समस्तीपुर, बिहार, भारत

भारत में वृद्धजनों कीं सामाजिक सुरक्षा की समस्याः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मधु कुमारी

सारांश
भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक युवा आबादी है, लेकिन वृद्धावस्था के लगभग 8 प्रतिशत लोगों का घर है। वृद्धावस्था का दुर्व्यवहार आजकल परिवार से दूर होने, महत्व कम करने और बीमारियों के कारण एक आम दृश्य है। उनकी शारीरिक अक्षमता, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और प्रियजनों द्वारा एकांतवास के कारण हत्या, चोट, डकैती जैसे अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एनसीआरबी 2017 के आंकड़ों के अनुसार 2014 के आंकड़ों की तुलना में बुजुर्गों के खिलाफ 9.7 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराधी आमतौर पर उनके रिश्तेदार होते हैं जिन पर वे निर्भर होते हैं। हालाँकि बुजुर्गों के उत्पीड़न से निपटने के लिए कई कानून हैं, फिर भी कुछ पहल करने की ज़रूरत है। इसलिए, इस पत्र में बुजुर्ग दुरुपयोग, इसके प्रकार और कारणों के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग उत्पीड़न के संबंध में विधायी रूपरेखा और राहत प्रदान करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा की गई है। अंतिम में कुछ समुदाय आधारित पहल जैसे कुछ सुझाव देने की कोशिश किया गया है। यहां पर माध्यमिक डेटा को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और हेल्प एज इंडिया (भारत में एब्यूज, 2018) की रिपोर्टों से लिया गया है और बुजुर्गों के शिकार पर प्रकाशित केस कार्यवाही और शोध पत्रों की समीक्षा की गई है। यद्यपि बुजुर्गों के उत्पीड़न से संबंधित कई विधायी प्रावधान हैं, फिर भी समुदाय के पुलिसिंग, बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता और ऐसे मुद्दों के बारे में संवेदनशील कार्यक्रमों के बारे में कुछ समुदाय आधारित पहल करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्दः वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा, दुर्व्यवहार, आश्रित, बुजुर्ग पीड़ित

प्रस्तावना
सैद्धांतिक दृष्टिकोण "वे अपने जीवन के गोधूलि में छोड़ दिया जा करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती" आज भारत की आबादी संक्रमण की अवधि से गुजर रही है। समाज में वृद्ध लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई पर्याप्त और सुरक्षित आय नहीं है। भारतीय समाज में माता–पिता अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा अपने बच्चों की परवरिश के लिए खर्च करते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने बुढ़ापे में उन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता आजकल बुजुर्गों के दुर्व्यवहार का एक बड़ा कारण है क्योंकि उनके बच्चे उन्हें एक बोझ मानते हैं और कई मामलों में वे उनसे संपत्ति निकालने की कोशिश करते हैं।
भारतीय संस्कृति में, बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। लेकिन परमाणु परिवारों के उद्भव जैसी सामाजिक संरचनाओं में बदलाव के कारण, इन बुजुर्गों द्वारा कामकाजी व्यक्तियों को युवाओं द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आजकल, केवल वे ही आत्म–निर्भर हैं और उनके पास कचरे की तरह सामाजिक सुरक्षा का एक स्रोत है, जो किसी के लिए किसी काम के नहीं हैं। "दुरुपयोग" शब्द बहुत ही सामान्य है और इसके विभिन्न अर्थ हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और फ़िजूल की गालियाँ शामिल हैं। "ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्ड पीपल इन इंडियाः ए रियलिटी चेक" की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक 1/3 वर्ष की आयु के लोग अपने जीवन में एक या अधिक तरह की गालियों का सामना करते हैं। कई तरह की गालियाँ हैं। जिनमें से पाँच मुख्य हैं। वो हैं

- शारीरिक शोषण
- मानसिक शोषण
- वित्तीय दुरुपयोग
- यौन शोषण और

- उपेक्षा

हेल्प एज इंडिया 2018 सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया था कि आजकल भारतीय परिवार की सेटिंग में दुरुपयोग के 3 रूप बहुत आम हैं। सबसे पहले परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा अपमान किया जाता है, जो सबसे अधिक यानी 56 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। दूसरा मौखिक दुर्व्यवहार है जो ज्यादातर बेटे और बहू द्वारा किया जाता है, जो कुल का 49 प्रतिशत हिस्सा है और तीसरा उपेक्षा है जो भौतिक रूप से या प्रौद्योगिकी के मामले में हो सकता है, अर्थात मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग जो कि 33 प्रतिशत है। बुढ़ापे के दुरुपयोग के मुख्य कारण परिवार और रिश्तेदारों पर वित्तीय निर्भरता है। दूसरे, युवा पीढ़ी में व्यक्तित्व की बढ़ती भावना। चूंकि आजकल की युवा आबादी अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनकी जीवन शैली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती है, वे बड़ों को अपनी स्वतंत्रता पर बोझ और प्रतिबंध मानते हैं। एक अन्य कारण बड़ों की अधिक संपत्ति और धन पाने की स्वार्थी इच्छाएँ हैं। अंत में, जीवन में निराशा और असफलताओं में से कई लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कमजोरों पर हावी होने और दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं।

बुजुर्गों के शिकार पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपाय भारतीय संविधान के तहत बुजुर्गों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। यद्यपि वे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा हैं, जो प्रकृति में अप्राप्य हैं, हालांकि कई मामलों में हमारी न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने के लिए उनकी व्याख्या की जाती है। सामान्य आबादी के कल्याण की उन्नति के लिए कदम उठाना राज्य का पहला कर्तव्य है। आगे बेरोजगारी और बुढ़ापे के मामलों में राज्य से काम करने और सहायता का अधिकार। व्यक्तिगत कानूनों के तहत ओल्ड के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। उदाहरण के लिए, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत, आश्रित माता–पिता के रखरखाव और कल्याण के लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आश्रितों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी बनाई जाती है। इसी तरह, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वयस्कों को अपने आश्रित माता–पिता को बनाए रखने के लिए बाध्य किया जाता है, जिनके पास आय का स्रोत नहीं होता है। मुल्ला के अनुसारः क) एक बच्चा जिसे बुनियादी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वह बिना किसी संदेह के अपने गरीब चौकीदारों को रखेगा, इस बात के बावजूद कि सभी संभावनाएं अंतिम रूप से अपने लिए कुछ सुरक्षित कर सकती हैं। (इ) वैसे भी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नौजवान अपनी माँ को बिना किसी संदेह के रखेगा, यदि माँ गरीब है, तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ईसाई और पारसी कानून के तहत, हालांकि 60 साल से ऊपर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत संरक्षण का दावा कर सकते हैं। चूंकि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार खंडित हैं, इसलिए 2007 में सरकार द्वारा एक अलग कानून पारित किया गया था, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बुजुर्गों के दुर्व्यवहार के मामले को स्थगित करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। इसमें बेटे / बेटी को बुजुर्ग माता–पिता के भरण–पोषण का निर्देश देने की शक्ति है। यदि बेटा / बेटियां न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, तो अधिनियम में विशिष्ट दंड प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। आवेदन जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, जो उचित जांच के बाद, रखरखाव के आदेश को पारित करते हैं। बुजुर्ग माता–पिता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी आवेदन दायर किया जा सकता है। कानून की प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए अधिनियमन भी छळव की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

1999 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने वृद्ध लोगों को निम्नलिखित सहायता देने के लिए वृद्ध व्यक्तियों (छच्व्) पर राष्ट्रीय नीति पेश की।

- वृद्धावस्था पेंशन योजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट
- उत्तरोत्तर तैयार लोगों से संपर्क करने के लिए पीडीएस बनाएं
- मानव प्रशासन, जिरियाट्रिक्स देखभाल, मानसिक भलाई संगठनों में समन्वय, कार्यस्थलों का समन्वय
- अनुदान, भूमि एनजीआई को रियायती दरों पर और निजी संकट सुविधाओं को अधिक तैयार व्यक्ति को कुशल और विशिष्ट विचार देने के लिए देता है
- केबिन की योजनाओं में 10 प्रतिशत घरों का निर्माण और क्रेडिट तक बुनियादी पहुंच
- अधिक तैयार व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए केबिन क्षेत्रों का लेआउट मुश्किल है
- संपत्ति–व्यापार, परिवर्तन, संपत्ति शुल्क, आदि के उदाहरणों का त्वरित आदान–प्रदान
- रैंक होम, डे–केयर सेंटर, मल्टी–ऑर्गनाइजेशन लोकल सेंटर, आउटकॉम्प्लिश ऑर्गनाइजेशन, फेल से संबंधित सहायक उपकरण और उपकरणों की आपूर्ति, आदि में सुधार / बैकिंग के लिए सहायता।
- तेजी से बसे हुए व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी वित्त की स्थापना करना

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम यूओआई में पहली बार, एससी ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों की दुर्दशा को पहचाना और कहा कि इसे मान्यता दी जानी चाहिए और इसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए एक फैसले में कहा कि वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण के तहत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत 'अंतरिम 'निष्कासन की मांग कर सकते हैं। पुराने कर्नाटक उच्च न्यायालय को गरिमा प्रदान करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों द्वारा कमोडिटी या चैटटेल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर से दर्शन बनाम सरकार छब्ज दिल्ली और अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि रखरखाव के लिए दावा नहीं करना चाहिए कि अपमानजनक बच्चों को बाहर निकालना चाहिए; माता–पिता पैतृक गुणों से कानूनी उत्तराधिकारियों को बेदखल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माता–पिता बीमार हैं, तो रखरखाव न्यायाधिकरण को कानूनी उत्तराधिकारी के निष्कासन का आदेश दिया जाता है। (१प्रपदह) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि माता–पिता के रखरखाव और कल्याण के बारे में कम जागरूकता है और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य के लिए आदेश जारी किया। अगर यह समर्पित कल्याण खंड को सहन नहीं करता है तो गिफ्ट डीड को निरस्त माना जाता है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए भी वे अधिनियम के तहत लाभ का दावा कर सकते हैं, हमीना कांग बनाम डी.एम. चंडीगढ़ डी.एस. माने बनाम लीलाबाई शिवाजी माने और अन्य में, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि कोई भी बच्चा अपने घर में माता–पिता, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकता है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव, भाई–बहनों के

बीच संपत्ति विवाद में उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मौजूदा मुद्दे

यद्यपि समय और फिर से विधायिका ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई प्रावधान लाए हैं। यहां तक कि न्यायपालिका ने भी उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। फिर भी किसी भी समस्या को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कारक नियमों, विनियमों और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन है। जैसे, हालांकि विधायिका ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 को पारित कर दिया है, फिर भी कई लोग ऐसे प्रावधानों से अनजान हैं। इसलिए उसी के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। एक और दबाव की समस्या यह है कि कई बार कई वरिष्ठ नागरिक अपने परिवार की प्रतिष्ठा के साथ–साथ अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर वित्तीय निर्भरता के डर के कारण किसी भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं करते हैं।

निष्कर्ष

समस्या यह है कि कई बार कई वरिष्ठ नागरिक अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों पर वित्तीय निर्भरता के डर के साथ–साथ अपने परिवार की प्रतिष्ठा के डर से किसी भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए इस तरह के मुद्दों के बारे में सामुदायिक संवेदनशीलता कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है एक और व्यवहार्य समाधान सामुदायिक पुलिसिंग का है, जो तीन अलग–अलग तरीकों से डर को कम कर सकता है। पुलिस को शहर पुलिस द्वारा तैयार किए गए पड़ोस कार्यक्रमों को बाहर लाना चाहिए। पुलिस की निगरानी गलत क्षेत्रों में वृद्धि की जानी चाहिए। स्वयंसेवक खंड की सहायता से, पुलिस को उन क्षेत्रों और बस्तियों को पहचानना चाहिए जहां अधिक वृद्ध व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति अधिक है और वे अकेले या जीवन साथी के साथ रहते हैं। इन राज्यों के व्यावसायिक क्षेत्रों, खुले पार्कों और मोहल्लों में क्रमबद्ध तरीके से साधारण जाँच की जानी चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों को संभावित खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे निवारक कदम उठा सकें। पुलिस को एक अधिक स्थापित फोन लाइन स्थापित करनी चाहिए जहां वरिष्ठ नागरिक अपने मुद्दों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुलिस को अकेले रहने वाले वृद्ध लोगों के जीवन और संपत्ति की भलाई के लिए पहल करनी चाहिए। पुलिस को अवांछनीय घटकों की जांच के लिए दिन और रात की घड़ी का निर्देश देना चाहिए।

संदर्भ

1. भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, 2016, भारत में बुजुर्ग।
2. भारत में वृद्ध लोगों के मानवाधिकारों पर एगवेल स्टडीः ए रियलिटी चेक, 2014।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2002, बुजुर्गों का दुरुपयोग, हिंसा और स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट में पीपी 123–45।
4. हेल्प एज इंडिया रिपोर्ट, 2018, भारत में एल्डर एब्यूज,
5. हेल्पएज इंडिया, 2011, भारत में एल्डर एब्यूज और क्राइम।
6. शर्मा, मोनिका, 2016, चंडीगढ़ में, बच्चों को संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने के लिए 2007 के बुजुर्ग कानून का उपयोग। हिंदुस्तान टाइम्स, 11 जुलाई 2016. अक्टूबर 2019
7. अभ्यंकर, गिरीश, (द.क) भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ों की स्थिति
8. अनुच्छेद 38, भारत का संविधान
9. अनुच्छेद 41, भारत का संविधान
10. धारा 20, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम
11. धारा 21, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम
12. भारत का राजपत्र, (2007) रखरखाव और कल्याण माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007।